भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 511
दिनांक 06 फरवरी, 2025

बायोडीजल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए फीडस्टॉक बेस का विस्तार

511. **श्री आलोक शर्मा:**
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा:
श्री दर्शन सिंह चौधरी:
श्री शंकर लालवानी:
श्री शेर सिंह घुबाया:
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री नव चरण माझी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में उत्पादित किए जा रहे बायोडीजल की राज्यवार मात्रा सहित फीडस्टॉक बेस की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा बायोडीजल उत्पादन के लिए फीडस्टॉक बेस का विस्तार करने हेतु किन्हीं अन्य स्रोतों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कृषि अपशिष्ट से बायोगैस का उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या बायोडीजल उत्पादन में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कोई संवर्धनात्मक योजनाएं तैयार की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र की कितनी कंपनियों ने उक्त परियोजना में निवेश किया है;

(छ) क्या सरकार की ओडिशा के मयूरभंज जिले में नए एथेनॉल संयंत्र की स्थापना करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) क्या सरकार का बायोडीजल उत्पादन में सरकारी –निजी भागीदारी मॉडल अपनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग) राष्ट्रीय जैव ईंधन-2018 नीति, जिसे वर्ष 2022 में संशोधित किया गया, में जैव-डीज़ल उत्पादन के लिए विभिन्न फीडस्टॉक की पहचान की गई है, जिसमें अन्य बातों के अलावा गैर-खाद्य तिलहन, प्रयुक्त खाना पकाने का तेल (यूसीओ), पशु वसा, अम्लीय तेल, कम अवधि की गैर-खाद्य तेल समृद्ध फसलें, शैवाल फीडस्टॉक

आदि शामिल हैं। वर्तमान में, जैव-डीज़ल की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के साथ 107 संयंत्र पंजीकृत हैं। इन संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा उनकी उत्पादन क्षमता के साथ नीचे दिया गया है:

राज्य	संयंत्रो की संख्या	क्षमता* (केएल प्रति दिन)
आंध्र प्रदेश	8	2198
असम	1	23
गुजरात	19	1777
हरियाणा	4	143.5
झारखंड	2	100
कर्नाटक	4	701
मध्य प्रदेश	5	116
महाराष्ट्र	7	244.5
ओडिशा	2	60
पंजाब	1	10
राजस्थान	17	1306
तमिलनाडु	6	1275
तेलंगाना	6	168
उत्तर प्रदेश	18	957
पश्चिम बंगाल	7	1560
कुल योग	107	10639
*नाम प्लेट क्षमता (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी 'प्रचालन सहमति' के अनुसार)		

(घ) सरकार ने दिनांक 1.10.2018 को कृषि-अवशेषों सहित विभिन्न अपशिष्ट/बायो-मास स्रोतों से संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) के उत्पादन और उपयोग के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से सतत (किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प) पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता और फीड स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर देश भर में सीबीजी संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। तेल और गैस विपणन कंपनियाँ (ओजीएमसीज) अर्थात आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, गेल और आईजीएल आगे के विपणन के लिए सीबीजी की खरीद के लिए उद्यमियों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करती हैं।

(ङ) और (च) सरकार ने जैव ईंधन उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत डीजल में जैव डीजल के मिश्रण / जैव डीजल की प्रत्यक्ष बिक्री का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित करना, 'परिवहन उद्देश्यों के लिए हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण हेतु जैव डीजल की बिक्री के लिए दिशानिर्देश-2019' को अधिसूचित करना, मिश्रण कार्यक्रम के लिए जैव डीजल की खरीद के लिए जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, जैव-डीजल सहित उन्नत जैव ईंधन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु "प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन - वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना" 2019 को अगस्त 2024 में संशोधित किया गया है।

(छ) एथेनॉल उत्पादन संयंत्र उद्यमियों/कंपनियों/सहकारी समितियों आदि द्वारा उनकी निवेश योजनाओं के अनुसार परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर स्थापित किए जाते हैं।

(ज) परियोजना के व्यावसायिक/आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर परियोजना प्रस्तावकों द्वारा निजी क्षेत्र में बायो-डीजल उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। वर्तमान में, बायो-डीजल उत्पादन के लिए पीपीपी मॉडल अपनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

****